Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : Economics
Research Link - 155, Vol - XV (12), February - 2017, Page No. 106-108
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

दुर्ग जिले के ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायत की भूमिका (पाटन विकासखण्ड के पतोरा पंचायत के संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र में दुर्ग जिले के ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायत की भूमिका का अध्ययन, पाटन विकासखण्ड के पतोरा पंचायत के संदर्भ में किया गया है। शोधपत्र का उद्देश्य न्यादर्श परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक संरचना का मूल्यांकन करना एवं ग्रमीण विकास के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में ग्राम पंचायत की भूमिका का मूल्यांकन करना है। शोध अध्ययन की परिकल्पना यह है कि सभी लोगों को ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी है। अध्ययन प्राथमिक समंकों पर आधारित है। पंचायत का न्यादर्श अध्ययन है।

कु.कल्याणी* एवं डॉ.रक्षा सिंह**

प्रस्तावना :

भारत गाँवों का देश है। आज भी 68 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। अगर भारत को विकास करना है, तो गाँवों का विकास करना जरुरी है और गाँवों का विकास पंचायतों पर निर्भर करता है। पंचायती राज के बिना गाँवों का विकास अधूरा है। पंचायतों के माध्यम से ही गाँव में विभिन्न कार्यक्रम चलाये जाते हैं, जिससे गाँव का विकास हो सके। इसी सच्चाई को स्वीकार करते हुए हमारे देश की निर्माताओ द्वारा आजादी प्राप्ति के बाद से ही ग्रामीण विकास कार्यक्रमो की सूत्रीकरण तथा कार्यान्वयन किया गया है। अतः ग्रामीण विकास योजनाओं से उन सभी लोगो के भविष्य को सुधारने का प्रयास किया जाता है, जो गाँवों में रहते हैं।

दुर्ग जिले के पाटन विकासखण्ड में अनेक विकास कार्य चल रहे हैं। पाटन की पंचायतो में विकास कार्यो के लिए 18 लाख रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत् सी.सी. रोड निर्माण एवं सामुदायिक भवन निर्माण कार्य कराये जा रहे है। नल–जल योजना को प्राथमिकता से लिया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत् ग्रामीण क्षेत्रों में घर–घर शौचालय निर्माण में तेजी आई है। विधायक आदर्श ग्राम ढ़ौर, कौही, तर्रीघाट, खेली, पन्दर, बोरेंदा में 676 शौचालय बनाने की राशि स्वीकृत की जा चुकी है, जिनमें 103 शौचालय का निर्माण हो चुका है एवं 225 का कार्य जारी है। इसके अलावा ग्राम झीट, अचानकपुर, बोरिद, तेलीगुण्डरा एवं अमेरी में 994 शौचालय बनाया जाएगा। इस प्रकार पाटन विकासखण्ड में अनेक विकास कार्य चल रहे हैं।

शोध के उद्देश्य :

(1) न्यादर्श परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक संरचना का मूल्यांकन करना।

(2) ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में ग्राम पंचायत के भूमिका का मूल्यांकन करना।

शोध परिकल्पना :

हमारी शोध परिकल्पना यह है, कि सभी लोगों को ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी है।

अध्ययन क्षेत्र :

दुर्ग जिले के ग्राम विकास में ग्राम पंचायत की भूमिका का अध्ययन करने के लिए पाटन विकासखण्ड के पतोरा पंचायत को चुना अध्ययन हेतु चुना है।

अध्ययन पद्धति :

(1) अध्ययन प्राथमिक समकों पर आधारित है।

(2) पंचायत का न्यादर्श अध्ययन है।

उत्तरदाताओं की आयु संबंधी विवरण तालिका 1 द्वारा दिखाई गई है।

तालिका 1

क्र0	आयु वर्ग	न्यादर्श संख्या	न्यादर्श प्रतिशत
1	20–30	5	12.5
2	30–40	7	17.5
3	40–50	20	50
4	50–60	5	12.5
5	60–70	3	7.5
	योग	**40**	**100**

तालिका 1 के आधार पर यह विदित होता है कि आयु वर्ग 40–50 के उत्तरदाताओं का प्रतिशत ज्यादा 50 प्रतिशत है, जबकि 60–70 आयु वर्ग के उत्तरदाताओं का प्रतिशत मात्र 7.5 प्रतिशत है।

**शोधछात्रा, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)*
***शोध निर्देशक एवं प्राचार्य, शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाई (छत्तीसगढ़)*

इसका कारण यह है कि गाँव में 40–50 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या अधिक है और हमने अध्ययन में इन्ही कार्यशील लोगों को शामिल किया है।

उत्तरदाताओं में 80 प्रतिशत स्त्री उत्तरदाताओं एवं 20 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाताओं को शामिल किया गया है।

उत्तरदाताओं में अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिशत 42.5 है। 32.5 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य पिछड़ावर्ग के हैं एवं 25 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, जबकि सामान्य वर्ग के एक भी उत्तरदाता नहीं हैं। इसका कारण यह है कि ग्राम पतोरा में अनुसूचित जनजाति के लोगों की जनसंख्या अधिक है। लगभग 100 परिवार इसी वर्ग के है।

उत्तरदाताओं में 15 प्रतिशत कोष्टा जाति के, 5 प्रतिशत उत्तरदाता कुर्मी जाति के, 10 प्रतिशत तेली जाति के, 42.5 प्रतिशत उत्तरदाता गोढ जाति के, 22.5 प्रतिशत सतनामी जाति के हैं, जबकि सिर्फ 2.5 प्रतिशत उत्तरदाता ढीमर एवं गाढा जाति के हैं।

उत्तरदाताओं के शैक्षणिक स्तर संबंधी विवरण तालिका 2 द्वारा दर्शाये गए हैं।

तालिका 2

क्र0	शैक्षणिक स्तर	न्यादर्श संख्या	न्यादर्श प्रतिशत
1	निरक्षर	14	35
2	प्राथमिक	10	25
3	माध्यमिक	10	25
4	हाईस्कूल	2	5
5	हायर सेकेण्डरी	2	5
6	स्नातक	1	2.5
7	स्नातकोत्तर	1	2.5
	योग	**40**	**100**

तालिका 2 से स्पष्ट होता है कि 35 प्रतिशत उत्तरदाता निरक्षर हैं, 25 प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किये हैं, 25 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की है, 5 प्रतिशत उत्तरदाता ने हाईस्कूल की शिक्षा ली है, 5 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं, जो हायर सेकेण्डरी तक शिक्षित हैं तथा 2.5 प्रतिशत उत्तरदाता ने स्नातक की शिक्षा तथा 2.5 प्रतिशत उत्तरदाता ने स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है। इसका कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर लोग कृषि में लगे रहते हैं, अतः छोटी उम्र में ही कार्य में लग जाते हैं, जिससे वह आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं।

अध्ययनगत उत्तरदाताओं में 34 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित हैं, वहीं 2.5 प्रतिशत उत्तरदाता अविवाहित हैं, 7.5 प्रतिशत उत्तरदाता विधवा है तथा 5 प्रतिशत उत्तरदाता विधुर हैं। इसका कारण यह है कि गाँव के लोग छोटी उम्र में लगभग 16–17 साल में ही बच्चों की शादी कर देते हैं, जिससे विवाहितों की संख्या अधिक है।

तालिका 3 से ज्ञात है कि उत्तरदाताओं के व्यवसाय में 5 प्रतिशत लोग कृषि कार्य एवं 75 प्रतिशत मजदूरी करते हैं, जबकि पशुपालन, नौकरी, व्यापार/दुकान चलाने वालों का प्रतिशत कम है। इसका कारण यह है कि गाँव में अधिकतर लोग अशिक्षित एवं

तालिका 3 : उत्तरदाताओं के व्यवसाय संबंधी विवरण

क्र0	व्यवसाय	न्यादर्श संख्या	न्यादर्श प्रतिशत
1	कृषि	2	5
2	मजदूरी	30	75
3	प्रा.टीचर	2	5
4	सिलाई	2	5
5	व्यापार/दुकान	4	10
	योग	**40**	**100**

कम पढ़े लिखे रहते हैं। अतः ये लोग कृषि एवं मजदूरी ही कर सकते हैं, अन्य कुशलता वाले कार्य नहीं कर सकते हैं।

तालिका 4 : उत्तरदाताओं की पारिवारिक मासिक आय संबंधी विवरण

क्र0	पारिवारिक मासिक आय	न्यादर्श संख्या	न्यादर्श प्रतिशत
1	1000–2000	25	62.5
2	2000–3000	2	5
3	3000–4000	5	12.5
4	4000–5000	5	12.5
5	5000–6000	2	5
6	6000–7000	1	2.5
	योग	**40**	**100**

तालिका 4 से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं की मासिक आय 1000–2000 रुपये के बीच का प्रतिशत अत्यधिक 62.5 प्रतिशत है, जबकि सबसे कम आय 6000–7000 रुपये के बीच का प्रतिशत मात्र 2.5 है। इसका कारण यह है कि गाँव में अधिकतर लोग अशिक्षित एवं कम पढ़े–लिखे रहते हैं, ये लोग मजदूरी ही कर सकते हैं। अतः मजदूरी में 2000–4000 रुपये से अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती है।

तालिका 5 : ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रहे योजनाओं का मूल्याकंन

क्र0	योजनाएँ	न्यादर्श संख्या/प्रतिशत		कुल न्यादर्श
		हाँ	नहीं	
1	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण योजना	38(95)	2(5)	40(100)
2	इंदिरा आवास योजना	8(20)	32(80)	40(100)
3	मनरेगा योजना	34(85)	6(15)	40(100)
4	वृद्धावस्था पेंशन योजना	37(92.5)	3(7.5)	40(100)
5	विधवा पेंशन योजना	37(92.5)	3(7.5)	40(100)
6	अन्नापूर्णा योजना	38(95)	2(5)	40(100)
7	अन्त्योदय योजना	35(87.5)	5(12.5)	40(100)
8	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	40(100)	0	40(100)
9	स्मार्ट कार्ड योजना का लाभ	25(62.5)	15(37.5)	40(100)
10	सामाजिक सुरक्षा योजना	13(32.5)	27(67.5)	40(100)
11	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	10(25)	30(75)	40(100)
12	निःशक्त छात्रवृति योजना	8(20)	32(80)	40(100)
13	राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	12(30)	28(70)	40(100)
14	कृत्रिम उपकरण योजना	8(20)	32(80)	40(100)

नोट : कोष्टक में प्रतिशत को दर्शाया गया है।

तालिका 5 से स्पष्ट है कि 95 प्रतिशत लोगों का कहना है कि गाँव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत सडकों के निर्माण कार्य हुए हैं, जबकि 56 प्रतिशत लोगों का कहना हैं कि निर्माण कार्य नहीं हुए हैं। 20 प्रतिशत लोगों का कहना हैं कि इंदिरा आवास योजना का लाभ मिल रहा है, जबकि 80 प्रतिशत लोगों का कहना है कि इंदिरा आवास योजना का लाभ नही मिल पा रहा है। 85 प्रतिशत का कहना है कि मनरेगा योजना का लाभ मिल रहा है, जबकि 15 प्रतिशत लोगों का कहना है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला है, क्योंकि उनका जॉब कार्ड नहीं बना है। 95.5 प्रतिशत लोगों का कहना है कि वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल रहा है, जबकि 7.5 प्रतिशत लोगों का कहना है कि इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। 92.5 प्रतिशत लोगों को विधवा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, जबकि 7.5 प्रतिशत लोगों का कहना है कि विधवा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। 95 प्रतिशत लोगों का कहना है कि अन्नपूर्णा योजना का लाभ मिलता है, जबकि 5 प्रतिशत लोगों का कहना है कि इस योंजना का लाभ नहीं मिल रहा है।

85.5 प्रतिशत लोगों का कहना है कि अन्त्योदय योजना का लाभ मिलता है, जबकि 12.5 प्रतिशत लोगों का कहना है कि उन्हें इस योजना का लाभ नही मिल रहा है। सभी का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना का लाभ मिलता है।

62.5% लोगों ने कहा स्मार्ट कार्ड योजना का लाभ मिला है, जबकि 37.5% लोगों का कहना है कि उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक जरुरत नहीं पड़ी है। 32% लोगों ने कहा सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है, जबकि 67.5% लोगों का कहना है कि उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस योजना की जानकारी नहीं है। 25% लोगों ने कहा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ मिल रहा है, जबकि 75% लोगों का कहना है कि उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस योजना की जानकारी पंचायत द्वारा नहीं दी जाती है। 20% लोगों ने कहा निःशक्त छात्रवृति योजना का लाभ मिल रहा है, जबकि 80% लोगों का कहना है कि इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस योजना की जानकारी नहीं है। 30% लोगों ने कहा कि निःशक्त पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, जबकि 70% लोगों का कहना है कि इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस योजना का लाभ भेदभाव तरीके से पहुँचाया जाता है। 20% लोगों ने कहा कृत्रिम उपकरण योजना का लाभ मिल रहा है, जबकि 80% लोगों का कहना है कि इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस योजना की जानकारी देने में भेदभाव किया जाता है।

सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से संतुष्टि :

95% लोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण योजना के क्रियान्वयन से पूर्णतः संतुष्ट है, जबकि 2.5% आंशिक रुप एवं 2.5% लोग संतुष्ट नहीं हैं। 10% लोग इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन से पूर्णतः संतुष्ट हैं, जबकि 40% आंशिक रुप से एवं 50% लोग संतुष्ट नहीं हैं। मात्र 2.5% लोग मनरेगा योजना के क्रियान्वयन से पूर्णतः संतुष्ट हैं, जबकि 40% आंशिक रुप से एवं 50% लोग संतुष्ट नहीं हैं। 42.5% लोग वृद्धावस्था पेंशन योजना के क्रियान्वयन से पूर्णतः संतुष्ट है, जबकि 37.5% आंशिक रुप से एवं 20% लोग संतुष्ट नहीं हैं। 52.5% लोग विधवा पेंशन योजना के क्रियान्वयन से पूर्णतः संतुष्ट है, जबकि 35% आंशिक रुप से एवं 7.5% लोग संतुष्ट नहीं हैं। 82.5% लोग अन्नपूर्णा योजना के क्रियान्वयन से पूर्णतः संतुष्ट है, जबकि 15% आंशिक रुप से एवं 2.5% लोग संतुष्ट नहीं हैं। 95% लोग अन्त्योदय योजना के क्रियान्वयन से पूर्णतः संतुष्ट है, जबकि 5% आंशिक रुप से संतुष्ट हैं। 92.5% लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के क्रियान्वयन से पूर्णतः संतुष्ट हैं, जबकि 35% आंशिक रुप से एवं 7.5% लोग संतुष्ट नहीं हैं।

42.5% लोग स्मार्ट कार्ड योजना के क्रियान्वयन से पूर्णतः संतुष्ट हैं, जबकि 40% आंशिक रुप से एवं 7.5% लोग संतुष्ट नहीं हैं। मात्र 2.5% लोग सामाजिक सुरक्षा योजना के क्रियावयन से पूर्णतः संतुष्ट हैं, जबकि 5% आंशिक रुप से एवं 92.5% लोग संतुष्ट नहीं है। 2.5% लोग परिवार सहायता योजना के क्रियान्वयन से आंशिक रूप से संतुष्ट हैं एवं 97.5% लोग संतुष्ट नहीं है।

25% लोग निःशक्त छात्रवृति योजना के क्रियान्वयन से पूर्णतः संतुष्ट हैं, जबकि 32.5% आंशिक रुप से एवं 42.5% लोग संतुष्ट नहीं हैं। 77% लोग निःशक्त पेंशन योजना के क्रियान्वयन से पूर्णतः संतुष्ट हैं, जबकि 12.5% आंशिक रुप से एवं 10% लोग संतुष्ट नहीं हैं। 30% लोग विधवा पेंशन योजना के क्रियान्वयन से पूर्णतः संतुष्ट हैं, जबकि 37.5% आंशिक रुप से एवं 32.5% लोग संतुष्ट नहीं है।

संदर्भ :

(1) शुक्ला, डॉ.राजेश : शोध प्रकल्प, , सितम्बर 2004, अंक 28, पृ. 47–50.

(2) *श्रीवास्तव, डॉ. राजेश : शोध उपक्रम, अप्रैल 2005, छतीसगढ़ शोध संस्थान, रायपुर, पृ.10–12.*

(3) *अग्रवाल डॉ.दिनेश एवं डॉ.कविता : शोध उपक्रम, जनवरी–मार्च 2005, पृ. 20–24.*

(4) *दुबे, अरविन्द कुमार (2005) : एम.ए.अंतिम परीक्षा में अंशपूर्ति हेतु प्रस्तुत शोध प्रबंध, सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान केन्द्र, भिलाई नगर, पृ. 62.*

(5) *सिंह, डॉ.श्रीमती उषा एवं सिंह, एच.पी.सिंह (2006) : सहयोग दर्शन, पृ. 65–72.*

(6) *Shivastava, Prasant & Agrawal, S.K. : Shodh Prakalp, 2008, P. 5-10.*

(7) *Pyasi,V.K. & Kumar, K.S. : Shodh Prakalp, 2008, P. 10-14.*

❁ ❁